



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 2003/फाल्गुन 3, 1924

No. 5]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 2003/PHALGUNA 3, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएँ

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2003

आ. अ. 11.—यतः फरवरी, 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिये हुए साधारण निर्वाचन में, 273—जनरलगंज विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी, श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल को भारत निर्वाचन आयोग ने, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10(क) के तहत, दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के अपने आदेश सं० 76/उ०प्र०-वि०स०/2002 द्वारा, उक्त आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये, अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निरह घोषित कर दिया था; और

2. यतः श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल ने दिनांक 20 नवम्बर, 2002 के अपने अभ्यावेदन द्वारा आयोग को यह बताया कि उन्हें आयोग को कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी; और

3. यतः आयोग के दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के आदेश सं० 76/उ०प्र०-वि०स०/2002 को प्राप्त करने के पश्चात् श्री सुरेन्द्र मोहन

अग्रवाल ने आयोग से सम्पर्क किया और तब उन्होंने यह बताया कि उनको सम्बोधित सूचना उनके पुत्र श्री संजीव अग्रवाल ने प्राप्त की थी; और

4. यतः, श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल ने यह अभिवचन किया कि उनके पुत्र श्री संजीव अग्रवाल मानसिक रोग से पीड़ित हैं और यह कि श्री संजीव ने उन्हें आयोग की सूचना नहीं दी; और

5. यतः श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल ने उपरोक्त अभिवचन के समर्थन में सभी संबंधित चिकित्सा अभिलेखों को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आयोग उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करें; और

6. यतः, आयोग ने दिनांक 20 नवम्बर, 2002 के श्री अग्रवाल के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया और उक्त सुनवाई 13 जनवरी, 2003 के लिये निश्चित की; और

7. यतः 13 जनवरी, 2003 को श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप में सुना गया था; और

8. यतः प्रकरण के गुणावगुणों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में हुई असमर्थता साशयिक नहीं थी और यह उनके नियंत्रण में नहीं थी तथा उन पर धारा 10(क) के तहत थोपी गई निरहता उन पर नहीं थोपी जानी चाहिये थी।

9. अतः, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10क के तहत दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के आयोग के आदेश द्वारा श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल पर आरोपित निरर्हता को दिनांक 13 जनवरी, 2003 से शेष अवधि के लिये हटाता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/273/2002]

आदेश से,

ए० एन० झा, उप निर्वाचन आयुक्त

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 14th January, 2003

O. N. 11.—Whereas Shri Surendra Mohan Aggarwal, a contesting candidate for the General Election to Uttar Pradesh Legislative Assembly from 273-Generalganj Assembly Constituency, held in February 2002, was disqualified by the Election Commission of India for failure to file the accounts of election expenses vide its order No. 76/UP-LA/2002, dated 7th November, 2002, under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for three years from the date of that order on the basis of report of District Election Officer, Kanpur Nagar intimating non-submission of account of election expenses by the said candidate.

And whereas, Shri Surendra Mohan Aggarwal has submitted a representation dated 20th November, 2002 wherein he had submitted that he had not received any notice from the Commission.

And whereas, Shri Surendra Mohan Aggarwal, after receiving the Commission's Order No. 76/UP-LA/2002, dated 7th November, 2002, contacted the Commission and was told that the notice intended to be served on him was received by his son Shri Sangeev Aggarwal :

And whereas, Shri Surendra Mohan Aggarwal, had pleaded that his son Sanjeev Aggarwal is suffering from mental illness and that the notice was not given to him by Shri Sanjeev;

And whereas, Shri Surendra Mohan Aggarwal had submitted all relevant medical records in support of his claim and has requested the Commission to give him an opportunity of being heard in person;

And whereas, the Commission, after considering Shri Aggarwal's representation dated 20th November, 2002 had decided to afford him an opportunity of personal hearing and fixed the hearing for 13th January, 2003;

And whereas, Shri Surendra Mohan Aggarwal was accordingly heard in person on 13th January, 2003;

And whereas, after considering the case on its merits, the Commission has concluded that the failure to lodge the accounts of election expenses as required by law

by Shri Surendra Mohan Aggarwal was not intentional and was beyond his control and the disqualification imposed under section 10A of the Act on him should not have been imposed.

Accordingly, Election Commission, in exercise of its powers conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, hereby removes the disqualification of Shri Surendra Mohan Aggarwal imposed upon them by the Commission's Order dated 7th November, 2002 under section 10A of the said Act, for the remaining period w.e.f. 13th January, 2003.

[No. UP-LA/273/2002]

By Order,

A. N. JHA, Dy. Election Commissioner

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2003

आ. अ. 12.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग कर्नाटक सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री दिलीप राउ, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री अभिजीत दासगुप्ता, आई. ए. एस. (के. एन. : 1975) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अभिजीत दासगुप्ता, कर्नाटक सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अभिजीत दासगुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पद पर कार्य करते हुए कर्नाटक सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/कर्ना./2003-का. प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th February, 2003

O. N. 12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Karnataka hereby nominates Shri Abhijit Dasgupta, IAS (K N : 1975), as the Chief Electoral Officer for the State of Karnataka with effect from the date he takes over charge and until further orders *vide* Shri Dilip Rau, IAS.

2. Shri Abhijit Dasgupta shall cease to hold and hand over forthwith charge of all or any charges of work under the Government of Karnataka, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Abhijit Dasgupta while functioning as Chief Electoral Officer, Karnataka shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Karnataka except that he should be designated Secretary to the Government in-charge of Election Department in the State Secretariat.

[No 154/KT/2003-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2003

आ. अ. 13.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री सन्यसाची सेन, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री एसके. नुरुल हक, आई. ए. एस. (डब्लू बी : 1982) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री एसके. नुरुल हक, पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री एसके. नुरुल हक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल के पद पर कार्य करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/प. बं./2003-का. प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th February, 2003

O. N. 13. —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of West Bengal hereby nominates Shri Sk. Nurul Haque, IAS (WB : 1982), as the Chief Electoral Officer for the State of West Bengal with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Sabyasachi Sen, IAS.

2. Shri Sk. Nurul Haque shall cease to hold and hand over forthwith charge of all or any charges of work under the Government of West Bengal, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Sk. Nurul Haque while functioning as Chief Electoral Officer, West Bengal, shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of West Bengal, except that he should be designated

Secretary to the Government in-charge of Election Department in the State Secretariat.

[No 154/WB/2003-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

आ. अ. 14.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री रविन्द्र सिंह, आई. ए. एस. (उ०प्र० : 79) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री रविन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री रविन्द्र सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पद पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/उ. प्र./2003-का. प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, अवर सचिव

New Delhi, the 17th February, 2003

O. N. 14.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby nominates Shri Ravindra Singh, IAS (UP : 79), as the Chief Electoral Officer for the State of Uttar Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri Ravindra Singh shall cease to hold and hand over forthwith charge(s) of all or any charges of work under the Government of Uttar Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Ravindra Singh while functioning as Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Uttar Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in-charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/UP/2003-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.